International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

मध्यप्रदेश की कोरकू जनजाति की मूल समस्यायों का अध्ययन"

शोधार्थी - संध्या निर्वेल

शोध सारांश:-

भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों का पाया जाना हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश राज्य इसी धरोहर से सम्पन्न है। मध्यप्रदेश भारत का सर्वाधिक (21.1%, 1,53,16,784) अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें कोरकू जनजाति का स्थान पांचवां है। जनसंख्या की दृष्टि से इनकी जनसंख्या (जनगणना 2011) 7,31,767 (4.77%) हैं जो अधिकांशतः मध्यप्रदेश के दक्षिण के जिले - खंडवा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, खरगोन,बड़वानी में निवास करती हैं। ये जनजाति आधुनिक समाज से दूर जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। जिसके कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जनजाति अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, पलायन, भूमि अधिकारों संबंधित गंभीर समस्याओं से ग्रसित हैं। इनका जीवन अधिकांशतः कृषि तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं । बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता और भूमि अधिकारों की कमी के कारण इन्हें कई आर्थिक समस्याओं का जैसे बेरोजगारी के कारण गरीबी का, गरीबी के कारण ऋणग्रस्तता और कुपोषण की समस्या का सामना करना पड़ता हैं । अशिक्षा तथा जागरूकता की कमी से सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है। जिससे ये जनजाति अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। कुपोषण के कारण कोरकू जनजाति गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- **मूल शब्द** - कोरकू जनजाति, समस्याएं, गरीबी, ऋणग्रस्तता, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी

➢ प्रस्तावना:-

मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति अत्यंत ही पिछड़ी हुई जनजातियों में शामिल है। अधिकांशतः देखा गया है कि जनसंख्या बहुल जनजातियों पर अधिक शोध कार्य हुए हैं। जिन जनजातियों की जनसंख्या

कम होती है उन्हें बड़ी जनजातियों में गिन लिया जाता है जैसे कोरकू जनजाति गोंड जनजाति से संबंधित होने के कारण एक ही युग्म मान लिया जाता है।

- **उद्देश्य:-**

1) कोरकू जनजाति की समस्यायों को चिन्हित करना।

2) समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

कोरकू जनजाति की जनसंख्या कम है लेकिन ये जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, राजनैतिक नेतृत्व के स्तर में अत्यंत पिछड़ी हुई है। जिसके कारण ये जनजाति अन्य समाज से पृथक प्रतित होती है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण इन्हे कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है-

1. गरीबी- गरीबी जनजाति समुदाय का बड़ा अभिशाप हैं। वास्तव में देखा जाए तो गरीबी ही जनजाति समुदाय की समस्याओं का मूल तत्व है क्योंकि गरीबी अन्य समस्याओं को जन्म देती हैं -ऋणग्रस्तता, कुपोषण, अशिक्षा, भूमि हस्तांतरण, पलायन आदि समस्याओं का कारण गरीबी ही है।[1] हालांकि बंगाल टाइगर को बचाने के सरकारी प्रयासों के कारण भी कोरकू जनजाति को अपनी पैतृक भूमि का सीमित उपयोग, पलायन व गरीबी जैसी समस्याओं को बढ़ावा दिया। कोरकू जनजाति के लोग झूम खेती द्वारा खेतिहर मजदूरी तथा इसके अतिरिक्त वनोपज को बेचकर भी अपना जीवन यापन करती हैं।[2]

ये जनजाति अत्यंत मेहनती होने के बाद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ये अनाज के अभाव में पेट भरने के लिए " लचका" खाते है। घास - फूस की झोपड़ी तथा कच्चे मकानों में रहते हैं। [3] (गरीबी अभिशाप) गरीबी के कारण ही ये साहूकारों एवं ठेकेदारों से ऋण लेते हैं और उसे समय पर न चुकाने के कारण उनके ऋण के बोझ से दबे रहते हैं।

2. ऋणग्रस्तता- कोरकू जनजाति की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। इनकी आय से इनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी ठीक से पूरी नहीं पाती है। गरीबी की समस्या से ग्रसित कोरकू जनजाति ऋणग्रस्तता की जटिल समस्या का शिकार हो जाती हैं।[4]

इनमें बचत करने की प्रवृत्ति का सामान्यतः अभाव होता है। इसी कारण कोरकू जनजाति कुपोषण, भूखमरी, पलायन, स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं से जूझ रही हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिये कोरकू लोगो द्वारा कृषि भूमि, घर के आभूषण बेचकर, गिरवी रखकर, साहूकारों व रिश्तेदारों से ऋण लिया जाता है, जिसे चुकाने के लिए जागरूकता के अभाव में उनसे कई गुना ब्याज वसूला जाता है। ऋणग्रस्तता का अन्य कारण सामाजिक धार्मिक परंपराओं के निर्वाह की अनिवार्यता , महामारी तथा प्राकृतिक आपदाएँ, अशिक्षा, बेरोजगारी, संसाधनों का अभाव, जागरूकता की कमी भी हैं। इनके कारण कोरकू जनजाति ऋणग्रस्तता उभर नहीं पा रही है।[5]

जनजाति लोग अपनी गरीबी, बेरोजगारी तथा अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ऋण लेने के कारण साहुकार, बनिये लाभ उठाकर इनका शोषण करते हैं। ये शोषण कभी- कभी इस स्तर तक बढ़ जाता हैं कि जनजाति लोग इस दबाव के कारण आत्महत्या का रुख अपना लेते हैं।[6]

3. कुपोषण - वर्तमान में कारकू जनजाति में कुपोषण जैसी गंभीर समस्या भी तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। पहले के समय ये जनजाति समूह अपने परंपरागत अनाज का उपयोग करती थी जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते थे। इसलिए उस समय कुपोषण, कमजोरी जैसी समस्याएं नहीं थी। लेकिन वर्तमान में कोरकू जनजाति में लगभग 70% बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। क्याकि कुपोषण से ग्रसित बच्चों के परिवार गंभीर घरेलू खाद्य संकट से जूझ रहे है। इन्हें दो वक्त का पर्याप्त भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। वर्ष 1997 में सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेंहू, चावल, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल प्रदान किया जाता हैं। इस योजना के तहत 35 किलो राशन दिया जाता हैं, जो एक कोरकू परिवार की 15 दिन ही पूर्ति करता हैं। महिने के बाकि दिनों के लिए इन्हें बाहर हाट से महंगा अनाज खरीदना होता हैं जिनकी कीमतें उनकी पहुँच के बाहर होती हैं। इसलिए कोरकू लोग चावल की चुरी (फिनकी) खाने के लिए मजबुर हैं। मांग बढ़ने से धीरे-धीरे इसकी किमतों में भी वृद्धि हो रही हैं, फिर भी कोरकू लोग इसे खा रहे हैं क्योंकि इसे उबालकर मिर्ची की चटनी के साथ खाया जाता है। यदि यह अनाज खरीदते हैं तो उसके साथ दाल, सब्जी का खर्चा भी होता हैं इसलिए ये लोग फिनकी खाकर ही अपना जीवन

यापन कर रहे है। लगभग 2009-2010 से सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दालों की किमतों में भी वृद्धि हो रही है जिससे कोरकू जनजाति इसका सेवन न कर पाने से प्रोटीन की कमी से जूझ रहे है। पहले ये जनजाति परम्परागत मोटे व पौष्टिक अनाज कोदो, कुटकी, सांवरिया का सेवन करते थे किंतु जब से ये जनजाति धीरे - धीरे ये नकदी फसल की तरफ आकर्षित हो रहें हैं जिससे इनका घरेलू खाद्य संकट बढ़ रहा है। कोरकूओ का परम्परागत अनाज वर्षों तक खराब नहीं होता था जिससे जनजाति समूह खाद्यान्न संकट से भी सुरक्षित रहती थी। अब कोरकू जनजाति नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं क्योंकि मोटे अनाज की बिक्री कम हो गयी है। फसलो की लागत हर साल बढ़ रही हैं जिस कारण छोटे व सीमांत किसान पूरे वर्ष का खाद्यान्न नहीं उगा पाते । इसी कारण खाद्य संकट उत्पन्न होता है जो कुपोषण का विकराल रूप ले लेता है। जनजाति समुदाय में खासकर बच्चों और महिलाओं में कुपोषण अधिक पाया जाता हैं, जो उनकी शारीरिक स्थिति तो कमजोर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। अधिकांशतः महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है और इससे बिमारियों की संभावना भी बढ़ जाती हैं। जनजाति समुदाय के पास संतुलित आहार न होने के कारण उनके आहार में अक्सर कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी,राइबोफ्लेविन, प्रोटीन, आयरन की कमी होती हैं । जिसके कारण वे कुपोषण के दुष्चक्र में फंसते ही चले जाते हैं।[7]

4. अशिक्षा - वर्तमान आधुनिक समय में भी कोरकू जनजाति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसका कारण गरीबी और अशिक्षा है। यदि हम गरीबी का मूल कारण खोजे तो वह अशिक्षा होगा। ये जनजाति अशिक्षा के कारण जागरूकता की कमी होने से समाज में होने वाले परिवर्तनों से अनजान हैं। अशिक्षा एवं अज्ञानता आज भी जनजातियों के लिए अभिशाप बना हुआ हैं वे आज भी इससे मुक्त नहीं हो पाये हैं।[8] आर्थिक व सामाजिक पक्षों की तरह ही शिक्षा के क्षेत्र में जनजातियां भिन्न- भिन्न स्तर पर होती हैं। जनजाति क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न होते हुए भी शिक्षा के निम्न स्तर के कारण कोरकू जनजाति समाज से काफी पिछड़ी हुई है। जनजाति क्षेत्रों में बड़े व मध्यम दोनों ही प्रकार की कई परियोजनाएं जैसे - सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और छोटे उद्योग

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ये जनजाति समुदाय सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा हैं। इसके अतिरिक्त कोरकू जनजाति के विकास प्रशासन द्वारा कई शासकीय स्कूल व छात्रावास खोले गए है। इनके लिए निशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, भोजन की व्यवस्था की गई है जो कोरकू जनजाति के हित में है। लेकिन इन सुविधाओं के बाद भी कोरकू जनजाति क्षेत्र में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया है। गरीबी और ऋणग्रस्तता से ग्रसित कोरकू जनजाति अपने बच्चों स्कूल के स्थान पर काम करवाने में अधिक विश्वास रखती हैं। जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।[9]

जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण रोटी है। क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व को बनायें रखने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यदि इनके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद भी उन्हें मजदूरी करना पड़ती है इसी कारण बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्र में अशिक्षा का एक बड़ा कारण शिक्षा का माध्यम भी है क्योंकि छात्रों व शिक्षक के मध्य संवाद की समस्या बनी रहती है।[10]

5. बेरोजगारी - जनजातियों की अर्थव्यवस्था अन्य समाज से अलग होती है। इनकी निजी आवश्यकताएं सीमित होती हैं जो लगभग पूरी तरह से वनों पर निर्भर होती है। वर्तमान समय में सिमटते हुए वन तथा वनों पर प्रतिबंध से इन जनजातियों के अधिकारों को भी सिमित कर दिया गया हैं, जिससे ये जनजातियाँ मजदूरी व पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं । जनजाति लोगो में बहुत कम लोगों के पास कृषि भूमि होती है, यदि होती भी है तो वह बहुत कम उपजाऊ होती हैं। विकल्प के रूप में इनके पास मजदूरी तथा व वनोत्पाद के रोजगार का सहारा रहता है जिससे होने वाली आय इतनी कम होती है कि उससे इनकी नीजी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती।[11]

जनजातियाँ अन्य समस्याओं की ही तरह बेरोजगारी की समस्या से भी ग्रसित हो जाती है। ये जनजातियाँ जंगल व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है जिसके कारण इन क्षेत्रों में उद्योग व उचित रोजगार की संभावनाएं नहीं हो पाती हैं।[12]

हालहीं में अभी बेरोजगारी के स्तर पर डेटा निकाला गया जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में बेरोजगार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 3,36,950 (मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 13%) हैं जो पंजीकृत युवा आदिवासी बेरोजगार हैं।[13]

- **सुझाव:-**

1. क़ोरकू जनजाति की गरीबी की मूल समस्या के निराकरण के लिये इनके जनजाति क्षेत्रों में उचित रोज़गार की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए उन्हें समय - समय जानकारी दी जानी चाहिएं। उन्हें वनोत्पाद संबंधित छोटे - छोटे व्यवसायों के लियें जागरूक करना चाहियें।

2. कोरकू जनजाति की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देना चाहिए जिससे शिक्षा की तरफ उनका आकर्षण बढ़े। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के अभिभावकों को समय - समय पर शिक्षा की उपयोगिता तथा लाभ के विषय में जानकारी उपलब्ध करवायी जाना चाहिएँ।

3. कोरकू जनजाति के स्वास्थ्य सुधार के लिए परम्परागत अनाज की ओर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामाग्री तथा इनके अभाव से होने वाले कुपोषण, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए।

4. जनजाति वर्ग के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का उचित क्रियान्वयन अति आवश्यक है। योजनाओं का संबंधित क्षेत्र में होने वाले प्रभाव का भी समय-समय पर निरिक्षण किया जाना आवश्यक हैं।

5. सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं में होने वाले भृष्टाचार को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए । संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

6. युवा बेरोजगारों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार स्थानीय स्तर रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

➢ **निष्कर्ष:-**

वर्तमान आधुनिक युग में हमारा देश निरन्तर विकास की ओर अग्रसर हो रहा हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारें देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जनजाति समुदाय हैं जो अभी तक आधुनिकता की चका - चौंध से कोसों दूर अंधियारें में जीवन यापन कर रहा हैं। इन समुदायों के लिए संविधान में तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है किंतु इन योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होने से तथा अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण आपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हैं।

➢ **संदर्भ सूची:-**

1. शाक्या, ललिता (2018)," कोरकू जनजाति के सांस्कृतिक परिवर्तन एवं निरंतरता का अध्ययन"

2. www.britannica.com, "कोरकू जनजाति संस्कृति"

3. गरीबी के अभिशाप से ग्रस्त "कोरकू आदिवासी समुदाय", www.themahamaya.com

4.शाक्या, ललिता (2018)," कोरकू जनजाति के सांस्कृतिक परिवर्तन एवं निरंतरता का अध्ययन"

5. नागोरी, निकिता (2021)," कोरकू जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास में आधुनिकीकरण के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (खंडवा एवं बुरहानपुर जिले के विशेष संदर्भ में)"

6 .शर्मा, शैलेन्द्रकुमार, (2019)," अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख विशेषताएँ एवं समस्याएँ"

7.के, अनिल कुमार (2021), " भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समकालीन समस्याएं"

8.शाक्या, ललिता (2018)," कोरकू जनजाति के सांस्कृतिक परिवर्तन एवं निरंतरता का अध्ययन"

9.वर्मा, डॉ रिता (1994), "मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन-सामाजिक जीवन के विशेष संदर्भ में"

10 . के, अनिल कुमार (2021), " भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समकालीन समस्याएं"

11. कोष्टा, शैलप्रभा, (2011)," जनजातियों का व्यवसाय, उपभोग एवं जीवन स्तर (मण्डला जिले के संदर्भ में)

12.चौधरी, डॉ आशीषकांत,(2023)," जनजातीय शिक्षा की समस्या- मुद्दे और चुनौतियाँ"

13. हिन्दी सबरंग, (26 सितम्बर, 2022) "मध्यप्रदेश में 7.72 लाख रजिस्टर्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के युवा बेरोजगार - सरकार डेटा"